कारपोरेट हलचल

आइएफसीआइ ने लाभांश दिया

आइएफसीआइ लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी निदेशक मलय मुखर्जी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को 92.30 करोड़ रुपये का चेक बतौर लाभांश भेंट किया। 31 दिसम्बर, 2015 को समाप्त 9 माह की अवधि के लिए वित्तीय कार्य-निष्पादन के अनुसार आईएफसीआई ने इस अवधि के दौरान 438 करोड़ रुपए का निवल लाभ अर्जित किया और इसकी कारोबारी परिसम्पत्तियां एक वर्ष पहले के 29,458 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 दिसम्बर, 2015 को 34,715 करोड़ रुपए हो गईं।

एनटीपीसी में कार्यक्रम

सरकारी कंपनी एनटीपीसी ने पिछले दिनों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस अवसर पर कंपनी के निदेशक यू पी पणि ने कहा समाज के समेकित विकास के लिए सस्टेनेबल डवलपमेंट सबसे अहम है। इस संदर्भ में उन्होंने पर्यावरण नियमों का उल्लेख किया और कहा कि सख्त पर्यावरण नियम आज समाज की सबसे अहम जरूरत बन गये है। उन्होंने एनटीपीसी परियोजनाओं का खास तौर पर जिक्र करते हुए कहा कि पर्यावरण अनुकूल कचरा प्रबंधन तकनीकी को अपनाना होगा।

सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन में उल्लेखनीय योगदान व उत्कृष्टता के लिए स्वर्णिम पुरस्कारों की ज्यूरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए सुप्रीमकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आरसी लाहोटी। साथ में हैं पूर्व इस्पात सचिव पद्मभूषण मुरुग रजा, विख्यात मैनेजमेंट कन्सल्टेंट पद्मभूषण डा. एमबी अयरेया, पीईएसबी के पूर्व अध्यक्ष सी. फुनसोग, सेल के पूर्व अध्यक्ष अरविंद पांडे तथा स्कोप के महानिदेशक डा. यूडी चौबे।

एनटीपीसी के निदेशक (वित्त) समेत प्रमुख कलबों ने द्विवार्षिक तौर पर आयोजित होने वाली छठी एशियन माइनिंग कांग्रेस को संबोधित किया। इसका आयोजन दि माइनिंग, जियोलॉजिकल एंड मेटलर्जिकल इंस्टीट्यूट आफ इंडिया (एमजीएमआइ), कोलकाता ने किया था। सम्मेलन में भारत के अलावा आस्ट्रेलिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, चीन, अफगानिस्तान तथा ईरान के खनन उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

पूर्वोत्तर के लिए हाइड्रोकार्बन विजन 2030 के तहत तेल एवं गैस का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य है। इसके तहत इंडियन ऑयल ने बोंगाइगांव रिफाइनरी में इंप्रूव्ड-इंडेन मैक्सिमाइजेशन यूनिट की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इसकी घोषणा इंडियन आयल के निदेशक (रिफाइनरी) संजीव सिंह ने इंडियन आयल रिफाइनरियों के सर्वोच्च प्रबंधन को संबोधित करते हुए की।

पुरस्कार विजेता सीएसआर महिला उद्यमियों के साथ केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद।

श्री के.के. शर्मा ने गुरुवार को सीमा सुरक्षा बल के 23वें महानिदेशक का पद संभाल लिया। शर्मा राजस्थान कैडर के 1982 बैच के आईपीएस अधिकारी है। इससे पहले वह भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय और नागर विमानन मंत्रालय में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वह 28 सितंबर 2012 को बीएसएफ में इंस्पेक्टर जनरल के रूप में शामिल हुए थे और आईजी, कश्मीर सीमा का पद भी संभाल चुके हैं। पूर्व बीएसएफ महानिदेशक डीके पाठक की जगह पर आए शर्मा को अगस्त 2009 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा गया था।

ईरेडा सम्मानित

गैर पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए पिछले दिनों ईरेडा को देश के बिजली, कोयला और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री पीयूष गोयल ने सम्मानित किया। यह पुरस्कार बिजनेस के फोकस समिट में दिया गया। सम्मेलन में सौ से ज्यादा विशेषज्ञों, सरकारी व निजी कंपनियों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

जीएसएस स्कूल लंगड़ गुड़गांव, हरियाणा में पौधारोपण करते हुए सेंट्रल रेलवाइड वेयरहाउस कंपनी लि. (सीईआरसी) के प्रबंध निदेशक केयू यंकचेन

आरईसी ने दिया 718.52 करोड़ रु. अंतरिम लाभांश

रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लि. (आरईसी) ने वर्ष 2015-16 के लिए ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार को 718.52 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश दिया है। आरईसी के सीएमडी राजीव शर्मा ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल को अंतरिम लाभांश का चेक भेंट किया।

मारीशस के लिए पहला फास्ट पेट्रोल वेसेल

भारत-मारीशस रक्षा सहयोग में नया अध्याय जोड़ते हुए 29 फरवरी 2016 को गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर की पत्नी श्रीमती रिमता पारसेकर ने मारीशस कोस्ट गार्ड के लिए गोवा शिपयार्ड लि. (जीएसएल) में डिजाइन व निर्मित पहला फास्ट पेट्रोल वेसेल एमसीजीएस विक्ट्री (लंबाई 50 मीटर) लांच किया। इस अवसर पर मारीशस के उच्चायुक्त जगदीश्वर गोबर्धन, वास्को के विधायक कारलोस अल्मीडा समेत गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

वक्रांगी आइओसी के साथ खोलेगी आउटलेट

वक्रांगी लिमिटेड द्वारा इंडियन आयल कारपोरेशन (आइओसी) के साथ रणनैतिक गठजोड़ किया गया है। इसके तहत वक्रांगी इंडियन आयल के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में रिटेल आउटलेट्स स्थापित करेगा। वक्रांगी ने राजस्थान में इंडियन आयल के साथ मिलकर 3575 रिटेल आउटलेट केंद्र स्थापित किए हैं। इन क्षेत्रों के नागरिक वक्रांगी केंद्रों पर आसानी से जा सकेंगे तथा वहां ई-कामर्स, ई-गवर्नेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस तथा एटीएम जैसी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।

एनएलसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सरत कुमार आचार्य ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल को अंतरिम लाभांश का चेक सौंपते हुए। साथ में ऊर्जा सचिव अनिल स्वरूप (दाएं) और एनएलसी लिमिटेड के वित्त निदेशक राकेश कुमार (बाएं)।

इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक श्री केएल मूर्ति और मुख्य ग्राहक सहायता अधिकारी श्री दिनेश भसीन ने टाटा मोटर्स के लिए नए सर्वो तेल की उच्च रेंज का शुभारंभ किया।

बड़े ज्वैलर्स पर ही उत्पाद शुल्क का प्रस्ताव

फोटो : ध्रुव कुमार

12 करोड़ से कम कारोबार वाले ज्वैलर्स उत्पाद शुल्क से मुक्त

- किसानों की मदद करने के लिए लगाया है किसान कल्याण सेस
- मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने को घटेंगे कॉरपोरेट टैक्स

साक्षात्कार

बजट के कर प्रस्तावों का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव अमीर-गरीब सब पर पड़ता है। मोदी सरकार ने एतिहासिक कदम उठाते हुए किसानों की भलाई के लिए धनराशि जुटाने को किसान कल्याण सेस लगाया है। ईपीएफ और ज्वैलरी पर कर प्रस्तावों का विरोध भी हो रहा है। आखिर क्या खास है कर प्रस्तावों में और क्या हैं इसके मायने। इन सवालों का जवाब जानने को हमारे विशेष संवाददाता हरिकिशन शर्मा ने बात की राजस्व सचिव डा. हसमुख अढिया से।

पेश है मुख्य अंश :

■ आम बजट 2016-17 के कर प्रस्तावों में गांव और किसानों के लिए क्या है ?

-किसानों को परोक्ष करों के माध्यम से बड़ी राहत दी गई है। सभी सेवाओं पर 0.5 प्रतिशत किसान कल्याण सेस लगाया है जिसका पूरा उपयोग किसानों के लिए होगा। खाद में उपयोग होने वाले माइक्रो न्यूट्रिएंटस पर उत्पाद शुल्क 12.5 प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक मोटर शाफ्ट और सेंट्रीफ्यूगल पंप पर उत्पाद शुल्क 12.5 प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत कर दिया है। खेती में 50 प्रतिशत से अधिक ऐसे ही पंप का प्रयोग होता है। अब ये सस्ते हो जाएंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित किया गया है। इसके तहत रेफ्रिजरेटर कंटेनर पर छूट दी गई है। साथ ही नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डवलपमेंट जो कृषि मंत्रालय के अधीन है, उसे सेवा कर से छूट दी गई है। कोल स्टोरेज की सुविधा का विस्तार हो, इसके लिए करों में रियायत दी गई है।

■ क्या किसान कल्याण सेस पहली बार लगा है ?

-इतिहास की मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन शायद यह पहली बार होगा, जब सरकार ने किसानों के लिए धनराशि जुटाने को अलग सेस लगा है।

■ किसान कल्याण सेस से कितनी राशि आएगी ?

-हमने 0.5 प्रतिशत सेस लगाया है। इससे अगले वित्त वर्ष में 5,000 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है। यह किसानों से जुड़ी योजनाओं पर खर्च होने वाली धनराशि का एक हिस्सा होगी। सरकार ने किसानों से जुड़ी योजनाओं के लिए 80-90 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

■ कालेधन के खुलासे पर भी 7.5 प्रतिशत किसान कल्याण सरचार्ज लगाया है, इसका क्या मतलब है ?

-इसका मतलब है कि इससे जो राशि जुटाई जाएगी, उसका उपयोग भी किसानों के लिए किया जाएगा। अभी हमने अंदाजा नहीं लगाया है लेकिन जो राशि आएगी, वह काफी होगी।

■ किसान कल्याण सेस लगाने का विचार कैसे आया ?

-दो साल से मानसून खराब रहने से खेती पर संकट है। किसानों को बहुत तकलीफ हो रही है। इसमें हम कैसे सहायक हो सकते हैं, इसलिए हमने किसानों के लिए राजस्व की व्यवस्था करने के लिए अलग सेस लगाया है।

■ कर प्रस्तावों में रोजगार बढ़ाने के लिए क्या किया गया है ?

-हमारे कर प्रस्तावों के दो उद्देश्य हैं। पहला, विकास और रोजगार को कैसे बढ़ाया जाए और दूसरा, कर प्रशासन में कैसे सुधार हो। मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित किया गया है। इससे घरेलू उद्योगों की स्थिति सुधरेगी। अगर नई मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियां आती हैं तो उन्हें मात्र 25 प्रतिशत टैक्स देना होगा। उन्हें 25 प्रतिशत कॉरपोरेट टैक्स के लिए पांच साल इंतजार की जरूरत नहीं। इससे नया निवेश आएगा।

■ उद्योगों से टैक्स रियायतें वापस लेने का साहसिक कदम भी उठाया है, इससे कितना धन वापस आएगा ?

-उद्योग से टैक्स छूट वापस लेने की शुरुआत 1 अप्रैल 2017 से होगी। इससे पहले साल में तीन हजार करोड़ रुपये का फायदा होगा। इसके बाद यह फायदा बढ़ता जाएगा।

■ यानि आपने जो बुनियाद रखी है उसका दूरगामी फायदा होगा ?

-बिल्कुल। पूरा फायदा आने वाले वर्षों में मिलेगा। सरकार को फिलहाल कंपनियों को टैक्स छूट से 60 से 70 हजार करोड़ रुपये नुकसान हो रहा है। 2033 तक यह पूरा खत्म हो जाएगा।

■ आम लोग कर अधिकारियों से डरते हैं, इसे दूर करने को क्या कदम उठा रहे हैं ?

-हम अधिकारियों के विशेषाधिकार हैं घटाने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए पहले कर अधिकारियों को पेनाल्टी लगाने की पूरी आजादी थी। वह 100 प्रतिशत, 200 प्रतिशत या 300 प्रतिशत पेनाल्टी लगा सकते थे लेकिन हमने इस बार के वित्त विधेयक में इसे घटा दिया है। सूचना अधूरी देने पर 50 प्रतिशत पेनाल्टी लगेगी, गलत सूचना देने पर 200 प्रतिशत पेनाल्टी लगेगी जबकि 300 प्रतिशत पेनाल्टी की श्रेणी को हटा दिया है। पहले टैक्स अधिकारी अपनी मर्जी से ही 300 प्रतिशत पेनाल्टी लगा देते थे। इससे अदालत में टैक्स मामले बढ़ जाते थे। हम इस विशेषाधिकार को खत्म कर रहे हैं।

■ कर अधिकारियों की जवाबदेही तय करने को क्या कदम उठाए हैं ?

-अगले साल से सात शहरों में ई-असेसमेंट शुरू होगा। इसके तहत अगर कोई करदाता चाहता है तो आयकर विभाग उसका पूरा असेसमेंट ऑनलाइन ही करेगा। ईमेल का पूरा रिकॉर्ड हमारे सर्वर पर होगा। आयकर अधिकारी ने उस व्यक्ति से क्या पूछा, करदाता ने उसका क्या जवाब दिया। जवाब आने के बाद वह कितने दिन उस पर बैठा रहा। यह ऑनलाइन उपलब्ध होगा। इससे कर अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।

■ ईपीएफ पर टैक्स का काफी विरोध हो रहा है ?

-हमने टैक्स नहीं लगाया है, हमने यह कहा है कि जब आप रिटायर होते हैं तो 40 प्रतिशत धनराशि आप निकाल सकते है लेकिन बाकी 60 प्रतिशत आप एन्युटी में निवेश कीजिए ताकि आपको वृद्धावस्था में पेशन मिलती रहे। अगर लोग इस धनराशि को एन्युटी में डालेंगे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर एन्युटी में निवेश नहीं करेंगे तो इस पर टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री कह चुके हैं कि संसद में संसद में चर्चा के दौरान जो भी सुझाव आएंगे, उसके आधार पर इस पर विचार किया जाएगा।

■ ज्वैलर्स भी ज्वैलरी पर उत्पाद शुल्क का विरोध कर रहे हैं ?

-हर राज्य में ज्वैलरी पर वैट लगा हुआ है। अगर प्रत्येक राज्य में वैट लिया जा सकता है तो फिर उत्पाद शुल्क देने में क्या दिक्कत है। हर राज्य में वैट लगा है। अगर वे वैट दे रहे हैं तो उनका कोई केस नहीं बनता। हम यह शुरू कर रहे हैं, इसलिए शुल्क लगाने के लिए कारोबार की सीमी यानि थ्रेसहोल्ड लिमिट काफी अधिक रखी गई है। अगर ज्वैलर का टर्नओवर 12 करोड़ रुपये से अधिक है, तभी वह इसके दायरे में आएगा। इससे कम टर्नओवर होने पर उत्पाद शुल्क नहीं देना है। असल में ज्वैलरी पर टैक्स छोटे ज्वैलर्स पर नहीं, बड़े दुकानदारों पर लगाया जा रहा है जिनके बड़े-बड़े स्टोर हैं और करोड़ों में कारोबार है। सरकार सिर्फ एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क ले रही है।

■ विदेश से कालाधन निकालने में सरकार कितनी कामयाब रही ?

पिछले दो साल में सरकार ने छापेमारी कर 20 हजार करोड़ रुपये कालाधन पकड़ा है। छापेमारी में आरोपी इस राशि को स्वीकार कर चुके हैं। वित्त वर्ष 2014-15 और चालू वित्त वर्ष में दिसंबर तक कुल 850 सर्च किए गए जिसमें करीब 20,000 करोड़ रुपये कालाधन पकड़ा गया है। इसके अलावा 7500 सर्वे किए गए हैं जिसमें 18,000 करोड़ रुपये अघोषित आय का खुलासा हुआ है। इन सभी मामलों में अभी आकलन (एसेसमेंट) किया जा रहा है।

स्टील उद्योग के हालात सुधरे- साइरस मिस्त्री

जासं, जमशेदपुर : टाटा समूह के चेयरमैन साइरस मिस्त्री ने कहा है कि चीन से आयातित स्टील ने घरेलू स्टील सेक्टर के लिए परेशानियां बढ़ाई थीं। लेकिन केंद्र सरकार की मदद मिलने से हालात में सुधार हुआ है।

उन्होंने पिछले साल को चुनौतीपूर्ण करार देते हुए कहा कि टाटा स्टील ने इसका मजबूती के साथ सामना किया। इस दौरान ही कंपनी ने ओडिशा में कलिंगानगर प्लांट की शुरुआत की तो कंपनी क्षमता बढ़ाने में भी सक्रिय रही।टाटा स्टील के संस्थापक जेएन टाटा की 177वीं जयंती पर यहां आयोजित समारोह में आए मिस्त्री ने कहा कि अब स्थिति थोड़ी सामान्य हो रही है। बिष्टुपुर स्थित पोस्टल पार्क से उन्होंने शहरवासियों को संबोधित किया। बोले कि संस्थापक दिवस पर यहां आना उनके लिए गर्व की बात है।

राज्यों में मचेगी विदेशी निवेश लाने की होड़

केंद्र-राज्यों के बीच होगा निवेश का समझौता

- निवेश समझौता करने वाले राज्यों में ज्यादा निवेश संभव
- कंपनियों के हितों की रक्षा का वायदा करना होगा राज्यों को

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए अब देश के भीतर राज्यों में वैसी ही होड़ मचेगी, जैसा दो देशों के बीच बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लुभाने के लिए होती है। राज्यों को अब केंद्र के साथ एक निवेश समझौता करना होगा। इस समझौते के तहत उन्हें विदेशी कंपनियों के निवेश को हर तरह की सुविधा मुहैया कराने के साथ ही उनके हितों की रक्षा करने का वादा भी करना होगा। इसका नतीजा यह होगा कि जिन राज्यों के साथ केंद्र का समझौता होगा, विदेशी कंपनियों उनके यहां निवेश करने में ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगी। इस समझौते से केंद्र सरकार विदेशी कंपनियों के हितों की रक्षा की ज्यादा जिम्मेदारी राज्यों पर डाल रही है और किसी अनहोनी की स्थिति में विदेशी निवेशकों को कोई हानि होती है तो उसकी भरपाई राज्यों को करनी होगी।

विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक काफी दिनों से यह महसूस किया जा रहा था कि विदेशी निवेशकों के हितों से सीधे तौर पर राज्यों को जोड़ा जाना चाहिए। भारत सरकार कई देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौता (बीआइटी) कर चुकी है और कई देशों के साथ आगे होने वाले हैं। लेकिन इस समझौते को लागू करने की अधिकांश जिम्मेदारी राज्यों की होती है। ऐसे में यह फैसला किया गया है कि इन निवेश समझौते की रक्षा के लिए केंद्र और राज्यों के बीच भी समझौता किया जाएगा। राज्य समझौते के तहत विदेशी निवेशकों के निवेश व उनके प्रतिष्ठानों की रक्षा करने के लिए बाध्य होंगे। किसी नुकसान की स्थिति में उसकी भरपाई करना केंद्र के साथ राज्य की भी जिम्मेदारी होगा। इसके बाद विदेशी कंपनियां उन राज्यों में ही निवेश करना चाहेंगी जिन्होंने केंद्र सरकार के साथ निवेश समझौता किया है। ऐसे में राज्यों के बीच भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। सनद रहे कि भारत इस समय 83 देशों के साथ बीआइटी किए हुए है।

काला धन बढ़ाता है ज्वैलरी कारोबार

नई दिल्ली, प्रेट्र : सोने और हीरे के जेवरातों पर फिर से एक फीसद उत्पाद शुल्क लगाने के खिलाफ ज्वैलर्स की जारी हड़ताल के बीच सीबीईसी के एक बयान से नया विवाद खड़ा हो सकता है।

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के चेयरमैन नजीब शाह ने कहा है कि ज्वैलरी सेक्टर काले धन को बढ़ावा देता है। इसे टैक्स के दायरे में लाने की जरूरत है। उद्योग चैंबर एसोचैम की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शाह बोले कि ज्वैलरी सेक्टर को कर के दायरे में लाया गया है। दो साल पहले भी ऐसी कोशिश हुई थी, लेकिन इसे वापस ले लिया गया था। इस क्षेत्र में काफी बेहिसाब दौलत है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में ज्वैलरी पर एक फीसद उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया है।

सोने और हीरे के जेवरातों पर शुल्क को फिर से लगाने के प्रस्ताव के खिलाफ ज्वैलर्स तीन दिनी हड़ताल पर हैं। वे दो लाख और इससे अधिक के ट्रांजैक्शन पर पैन की अनिवार्यता के भी विरोध में हैं।शाह ने कहा कि जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर का 17 फीसद योगदान है। उद्योग का बड़ा हिस्सा टैक्स के दायरे से बाहर है।

अर्थसार

सेंसेक्स	24606.99	▲364.01
निफ्टी	7475.60	▲106.75
डॉलर	₹67.35	▼₹0.20
यूरो	₹73.30	▼₹0.06

(सराफा बाजार बंद)

तीसरे दिन भी बाजार में तेजी जारी

मुंबई, प्रेट्र : आम बजट के बाद से दलाल स्ट्रीट में सिलसिला तीसरे दिन भी जारी रहा। विदेशी संकेतों ने भी निवेशकों को लिवाली के लिए प्रेरित किया। इससे गुरुवार को बंबई शेयर बाजार (बीएसई) के सेंसेक्स 364.01 अंक यानी 1.5 फीसद उछलकर 24606.99 पर बंद हुआ। बीते दो सत्रों के दौरान भी इसमें करीब 1241 अंक की बढ़त दर्ज हुई थी।

इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 106.75 अंक यानी 1.45 फीसद चढ़कर 7475.60 पर बंद हुआ। राजकोषीय घाटा काबू में रहने से रिजर्व बैंक के लिए अपनी नीतिगत ब्याज दर में कटौती की गुंजाइश बनी है। निक्केइ का सर्विस सेक्टर इंडेक्स तीन माह के निचले स्तर पर आने से भी ब्याज दर घटने की उम्मीद बढ़ी है।

रुपया हुआ और दमदार

मुंबई : अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपये में मजबूती का क्रम लगातार पांचवें सत्र में मजबूती का क्रम जारी रहा। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 20 पैसे और उछल गया। इस दिन घरेलू मुद्रा 67.35 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुई। रुपये की इस तेजी के पीछे शेयर बाजार की तेजी के बीच बैंक और निर्यातकों की ओर से लगातार डॉलर बिकवाली मुख्य वजह रही।

ब्याज दर घटाने को आरबीआइ पर दबाब

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : वैसे तो ब्याज दरों को लेकर फैसला करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक स्वतंत्र है लेकिन सरकार की तरफ से इस बात का दबाब बढ़ा दिया गया है कि केंद्रीय बैंक को कर्ज को सस्ता कर औद्योगिक विकास दर को बढ़ाने में मदद करनी चाहिए।

वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने आज इस बारे में आरबीआइ को संबोधित करते हुए कहा कि देश में सस्ती ब्याज दर के माहौल के लिए अर्थव्यवस्था में आधारभूत स्थायित्व का होना बहुत जरूरी है। बजट के जरिये सरकार ने यह करने की कोशिश की है। इस वजह से ही राजकोषीय घाटे को भी काबू में रखने के लिए नया लक्ष्य तय किया गया है। जानकारों का कहना है कि अगले एक-दो दिनों के भीतर वित्त मंत्री अरुण जेटली की आरबीआइ गवर्नर डॉ. रघुराम राजन के साथ बैठक होने वाली है। इस बैठक में ब्याज दरों का मुद्दा निश्चित तौर पर उठेगा। बजट पेश करने के बाद से ही वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी लगातार यह कह रहे हैं कि उन्होंने मौजूदा औद्योगिक मंदी को दूर करने के लिए सरकार के स्तर पर जो हो सकता है, वह कर दिया है। आरबीआइ की तरफ से पहले राजकोषीय घाटे के बढ़ने को लेकर चिंता जताई गई थी लेकिन सरकार ने वर्ष 2016-17 के लिए 3.5 फीसद का राजकोषीय घाटे का लक्ष्य तय कर यह संकेत दिया है कि वित्तीय प्रबंधन को लेकर भी सतर्कता बरती जा रही है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया विजय माल्या को झटका

नहीं मिली राहत

- अदालत ने उद्योगपति की याचिका पर सुनवाई से किया इन्कार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : यूबी ग्रुप के प्रमोटर विजय माल्या के पीछे बैंक हाथ धोकर पड़ गए हैं, मगर उन्हें कहीं से राहत मिलती नहीं दिख रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उनकी याचिका को सुनने से इन्कार कर दिया है। इसमें माल्या ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) द्वारा उन्हें इरादतन डिफाल्टर घोषित करने के निर्णय को चुनौती दी थी।

खास बात यह है कि इसी मामले में एसबीआइ ने बीते दिन कर्ज वसूली ट्रिब्यूनल में अर्जी देकर माल्या की गिरफ्तारी और उनका पासपोर्ट जब्त करने की मांग की थी। किंगफिशर पर सभी बैंकों का करीब 7,800 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है। उद्योगपति माल्या को एसबीआइ ने बीते साल 15 नवंबर को इरादतन कर्ज न चुकाने वाला (विलफुल डिफॉल्टर) घोषित कर दिया था। पंजाब नेशनल बैंक समेत कई और बैंक भी पहले ही उन्हें विलफुल डिफॉल्टर करार दे चुके हैं। एसबीआइ के कदम को माल्या ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई कर रही पीठ ने माल्या के वकील से कहा कि इस मसले को लेकर उचित फोरम के पास जाएं। अदालत का रुख देखते हुए वकील ने अर्जी वापस ले ली। माना जा रहा है कि माल्या अब बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। किंगफिशर एयरलाइंस को दिए गए इस कर्ज को नहीं चुकाने का मामला लेकर बीते दिन एसबीआइ डीआरटी, बेंगलुरु में पहुंच गया। बैंक ने अपनी अर्जी में कर्ज नहीं चुकाने वाले माल्या को गिरफ्तार करने के अलावा उनके पासपोर्ट की जब्ती और संपत्ति सार्वजनिक करने की भी मांग की है। इस अर्जी के खिलाफ माल्या के वकील ने याचिका दाखिल कर गिरफ्तारीव पासपोर्ट जब्त किए जाने की मांग का विरोध किया है।

किंगफिशर नहीं उड़ने का मलाल

नई दिल्ली, एजेंसियां : बैंक कर्ज नहीं लौटाने की वजह से भले ही विजय माल्या के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, मगर माल्या को इसका रत्ती भर मलाल नहीं है। उन्हें बस एक चीज का अफसोस है कि तेल इतना सस्ता है, इसके बाद भी उनकी यह एयरलाइन उड़ान नहीं भर पा रही है। वर्ष 2014 के बाद से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य लगभग 75 फीसद नीचे आ चुके हैं। माल्या ने कहा, 'ऐसा नहीं है कि एयरलाइंस बेवकूफी से बंद हो गई। इसके पीछे कारण हैं। मैंने देश की सबसे बड़ी बीयर कंपनी बनाई। मैंने ही भारत की सबसे बड़ी शराब कंपनी स्थापित की।'

गोल्ड बांड की तीसरी स्कीम जल्द लांच होगी

नई दिल्ली, प्रेट्र : पहले दो चरणों में 1050 करोड़ रुपये जुटा चुकी सरकार जल्दी ही तीसरे चरण की गोल्ड बांड स्कीम लांच करेगी। यह जानकारी आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने दी है। हम निश्चित तारीख नहीं बता सकते हैं लेकिन स्कीम इसी वित्त वर्ष के दौरान जल्दी ही आएगी। निश्चित तारीख से सोने के मूल्य में उथल-पुथल होने लगेगी। सरकार ने नवंबर में लांच पहले चरण की स्कीम में 246 करोड़ मूल्य का 915.95 किलो सोने का सब्सक्रिप्शन प्राप्त किया था।